सांध्य दैनिक 4PM

प्रेम का धागा नाजुक होता है। इसे तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना कठिन होता है और यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गाँठ पड़ जाती है।

-रहीम दास

मूल्य ₹ 3/-

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्षः 11 ● अंकः 35 ● पृष्ठः 8 ● लखनऊ, शुक्रवार, 7 मार्च, 2025

यूपी वारियर्स की प्लेऑफ की... 7 | बढ़ता जा रहा केंद्र व राज्यों... 3 | यूपी के गरीबों को नहीं मिल... 2

बिहार में अपराधों की बहार! तेजस्वी का करारा वार

दिया नया नारा, सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका-हारा

» सीएम नीतीश कुमार के गृह जनपद नालंदा में तलवे में कीले ठोकर महिला की हत्या से सनसनी

» नहीं चलेगा टायर्ड और रिटायर्ड सीएम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार चुनाव में पूर्व उप-मुख्यमंत्री और युवा राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक साथ नीतीश सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। तेजस्वी ने बिहार में हालिया अपराधिक घटनाओं पर नीतीश सरकार को घेरा है और कहा है कि सीएम खुद इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं कि अपराधी जेलों से कैसे बाहर आये। तेजस्वी ने नालंदा जिले में एक महिला की तलवे में कीलें ठोकर की गयी हत्या का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि बिहार में अपराधियों की बहार है। मुख्यमंत्री स्वयं अपराधियों को छुड़वाते हैं।

वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार राज्य देश का सबसे युवा प्रदेश है। यहां सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। इसलिए अब यहां टायर्ड और रिटायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के पटना में आयोजित हुए युवा चौपाल को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सरकार थोड़े दिन और रहेगी, तो पूरे बिहार को बीमार कर देगी। उन्होंने कहा, सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका-हारा है।

नहीं बता पाएंगे सभी मंत्रियों के नाम

उन्होंने कहा कि आज स्थिति ऐसी है कि मुख्यमंत्री से कोई पूछे कि अपने सभी मंत्रियों का नाम बताइए, तो वह नहीं बता पाएंगे। दो उपमुख्यमंत्री हैं एक लाउड माउथ और एक फाउल माउथ। मुख्यमंत्री दोनों उपमुख्यमंत्रियों का नाम भी नहीं जानते हैं। जब तक उन्हें लिखकर नहीं दिया जाए नाम नहीं बता पाएंगे। नीतीश कुमार को बिहार ने 20 साल दिया इन्होंने दो पीढ़ियों को बर्बाद किया है।

75 वर्ष का मुख्यमंत्री

तेजस्वी ने कहा कि हमें निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। क्या आपको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए? अब समय आ गया है कि हमें बिहार को नई गाड़ी से आगे ले जाना है खटारा गाड़ी से नहीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सवाल किया 25 साल वालों, क्या आपको 75 साल का सीएम चाहिए? बिहार में 25 साल की आबादी के लोगों की संख्या 58 फीसदी है।

मेरे पिता जी के बारे में गलत बात करते हैं नीतीश कुमार

तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि उन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश कुमार क्या कहते हैं, यह भूल जाइए। लेकिन, नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए कि उनसे पहले भी मेरे पिता दो बार विधायक और एक बार सांसद चुने जा चुके हैं। लालू यादव ने कई प्रधानमंत्री बनाए हैं। मैंने ही उन्हें (नीतीश कुमार) दो बार मुख्यमंत्री बनाया और उनकी पार्टी को बचाया।

सम्राट चौधरी ने किया पर्सनल अटैक

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पर्सनल अटैक करते हुए कहा कि उन्हें जो कुछ भी लिखकर दिया जाता है उसे सदन में आकर वह पढ़ देते हैं। इस दौरान सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब तारीफ की और कहा कि, उन्हें साल 2005 में खटारा गाड़ी मिली थी, जिसे उन्होंने मर्सिडीज में तब्दील किया। 20 सालों से वे बिहार को सींच रहे हैं। उनके नेतृत्व में बिहार हर मानकों पर तेजी से विकास कर रहा है।

नहीं लगेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस

उन्होंने घोषणा की कि जब बिहार में राजद की सरकार आएगी तो प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगेगा, बल्कि परीक्षा केंद्र तक आने और जाने का किराया भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में रिटायर्ड अधिकारियों के साथ खटारा मुख्यमंत्री हैं। इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।

सीएम के गृह जनपद में अमानवीयता की हदें पार

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से एक युवती के तलवे में नौ कीलें ठोककर हत्या करने की सूचना मिली है। यह घटना दुखद और काफी चिंतित करने वाली है। सरकार हत्यारों की पहचान कराकर जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की गारंटी करे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के बड़े-बड़े दावे करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में महिला उत्पीड़न की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रतिदिन हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट की घटनाएं घट रही हैं। विधि-व्यवस्था चौपट हो गई।

यूपी के गरीबों को नहीं मिल पा रहा इलाज : अखिलेश यादव

» बोले- भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एकबार फिर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा मुखिया ने कहा है कि भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब है। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और संसाधनों की भारी कमी है। गरीबों को दवा इलाज नहीं मिल पा रहा है। मरीज और तीमारदार इलाज के लिए भटक रहे है।

श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर झूठे दावे करती है। मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। प्रदेश के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज के नाम पर सिर्फ कुछ आधी-अधूरी बिल्डिंग बनी पड़ी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं।

सरकार के पास झूठे आश्वासन देने के सिवा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने आठ साल में स्वास्थ्य विभाग से लेकर पूरे तंत्र को बीमार बना दिया है। भाजपा की झूठ, लूट और बेईमानी से प्रदेश की जनता परेशान और त्रस्त है। भाजपा सरकार जनता की समस्या के समाधान करने, दवा, इलाज की व्यवस्था करने के बजाय विपक्षी दलों पर झूठे और अनर्गल आरोप लगाकर बदनाम करने का षड्यंत्र करती रहती है।

जताया शोक

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्रीअखिलेश यादव ने समाजवादी लोहिया वाहिनी सीतापुर के जिलाध्यक्ष मेराज अहमद की मौसी के निधन पर गहरा शोक जताया। श्री यादव ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। वहीं अमेठी जनपद के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लाक शुकुल बाजार के समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लाक अध्यक्ष भवानी प्रसाद मिश्र के निधन पर गहरा शोक जताया। अखिलेश यादव ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की।

पर्याप्त बजट नहीं दे रही सरकार

श्री यादव ने कहा कि सरकार अस्पतालों ओर मेडिकल कॉलेजों में संसाधनों, जांच, मशीनों तथा आधुनिक उपकरणों के लिए पर्याप्त बजट नहीं दे रही। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है। सरकार नाकाम हो गयी है। स्वास्थ्य विभाग को जो बजट मिलता है उसका भी बंदरबांट हो रहा है। पूरे विभाग में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार है। भाजपा सरकार का पूरा ढांचा ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। गंभीर मरीजों को जांच और इलाज के लिए लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ता था। पूरे सिस्टम से त्रस्त मरीज इलाज और जांच के लिए निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में जाने पर मजबूर है। वहां इलाज के नाम पर उनकी जेब काटी जाती है।

मजदूरों का हक मार रही भाजपा : अजय राय

» कांग्रेस का भाजपा पर वार, संसद से सड़क तक करेगी प्रदर्शन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ । राजधानी लखनऊ मेंकांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने मनरेगा मजूदरों की मजदूरी को लेकर भाजपा को घेरा। कहा कि भाजपा सरकार मजदूरों का हक मार रही है। यही वजह है कि आठ माह से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में वे होली त्योहार नहीं मना पाएंगे। तमाम मजदूरी महाकुंभ में भी नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजदूरों के भुगतान को लेकर संसद से सड़क तक प्रदर्शन करेगी।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 1 करोड़, 65 लाख, 11 हजार, 8 सौ 51 जॉब कार्ड धारक हैं। इसमें एक्टिव जॉब कार्ड धारकों की संख्या 1 करोड़, 9 लाख, 33 हजार, 3 सौ 96 हैं। लगभग एक करो? 10 लाख जॉब कार्ड धारकों को पिछले 9 दिसंबर 2024 से उनकी मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार नहीं कर रही है। इस समय मजदूरों की बकाया धनराशि 99.75 करोड़ रूपये है। जबकि अधिनियम में प्रावधान है कि मजदूर को अपनी मजदूरी करने के 15 दिन के अंदर उसके खाते में मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। अन्यथा नियम अनुसार .05 प्रतिशत प्रति विलंबित दिवस का हरजाना मिलना चाहिए।

मजदूरों का ईपीएफ का पैसा कहां गया

उन्होंने कहा कि इन संविदा कर्मियों को ईपीएफ का सामाजिक सुरक्षा कवच अप्रैल 2015 से ईपीएफ अधिनियम के अनुसार मिलना चाहिए, लेकिन आज तक कर्मियों के खाते में ईपीएफ का पैसा नहीं जमा हुआ। नतीजा यह है कि पिछले आठ वर्षों में 2000 से ज्यादा संविदा कर्मियों की मृत्यु हुई और उनके परिवारों को ईपीएफ का कोई लाभ नहीं मिल पाया। इस प्रकरण में सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात यह है कि ईपीएफ में नियोक्ता का जो 13 प्रतिशत अंश होता है वह भी संविदा कर्मियों के मानदेय से काटा जा रहा है। यह न सिर्फ नियम विरुद्ध है बल्कि यह भाजपा सरकार की संविदाकर्मी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।

आमजन को नहीं मिल पा रहीं बुनियादी सुविधाएं : मायावती

» भाजपा सरकार पर जमकर बरसीं बसपा प्रमुख

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा करते नहीं थकती है। लेकिन, आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद यहां लोगों को जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें पूरा नहीं हैं। उनकी जो दुर्दशा है वो किसी से छिपी नहीं है।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी धन की कमी नहीं है। लेकिन, इसका इस्तेमाल यहां के गरीब लोगों के हित, कल्याण और उनके जीवन सुधार में सही से नहीं हो रहा। यह काफी चिंताजनक बात है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में चार बार सरकार रही। हमने सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का एतिहासिक सुधार जमीन पर उतारकर दिखाया। वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

2007 की तर्ज पर 2027 में चुनाव जीतेगी बसपा

» बसपा के नये कोआर्डिनेटर बने बेनीवाल का दावा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के नये कोआर्डिनेटर बने रणधीर बेनीवाल का दावा है कि बसपा 2007 की तरह 2027 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है।

रणधीर बेनीवाल ने खुद को मिली जिम्मेदारी पर बहन मायावती का शुक्रिया कहते हुए भरोसा जताया है कि? ऐसा होगा।

उनके मुताबिक पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें निराश नहीं किया जाए। वो जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं, उनके दिशा-निर्देश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 2007 में बसपा की सरकार बनी थी, वैसे ही 2027 में भी हम जीत हासिल करेंगे। इसके लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है।

कुछ अपने ही लोग पार्टी को पहुंचा रहे नुकसान

पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हैं, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आकाश आनंद के इस बयान बेनीवाल ने प्रतिक्रिया देने से मना किया। उन्होंने कहा पार्टी का जो स्टैंड है हम उसके साथ हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मायावती ने जो भी आज तक निर्णय लिया है, वो पार्टी के हित में लिया है। मायावती अपने फैसले में न परिवारवाद न किसी बेनीवाल और न ही किसी बड़े पदाधिकारी या रिश्तेदार को देखती हैं।

एक व्यक्ति एक पद

बेनीवाल का दावा है कि मायावती की प्लानिंग 2007 की तरह चल रही है। इसी की तरह हम 2027 में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार की जगह रणधीर बेनीवाल को पार्टी का नया नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। आनंद कुमार पहले की तरह पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। बसपा मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार जिन्हें हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है जिसका स्वागत।

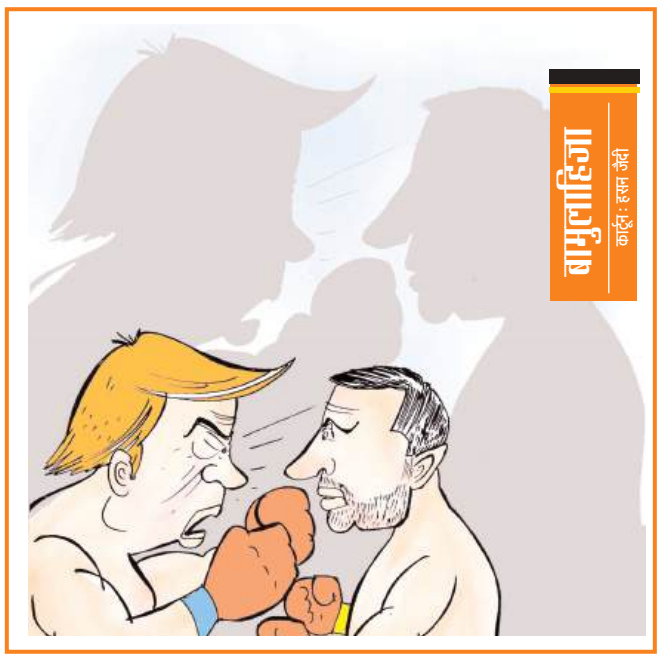

सीएम योगी की भी नहीं मानते अफसर

सिंचाई विभाग में गोरखधंधा

» सहायक अभियंताओं की मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जारी हुई थी लिस्ट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को नहीं मानते हैं। सहायक अभियंताओं की मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जारी हुई थी लिस्ट। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद भी विभागाध्यक्ष सहायक अभियंताओं की जारी कर रहे हैं सिंगल आदेश।

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रमुख सचिव अनिल गर्ग के बिना अनुमोदन के जारी हो रहा आदेश,जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 750 सहायक अभियंताओं की एक साथ अनुमोदन दिया गया था,मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और विभाग की छवि को धूमिल करने में लगे हैं । विभागाध्यक्ष,सरकार की मंशा के विपरीत चला रहे हैं सिंचाई विभाग को,सिंगल -सिंगल आदेश जारी करने का लिखित में नहीं लिया कोई आदेश,सिंगल आदेश निकलने से आसानी से कर रहे संशोधन,मुख्यमंत्री के यहां से पास हुई लिस्ट में किया जा रहा संशोधन,जलशक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव की छवि को किया जा रहा धूमिल,इससे पूर्व अवर अभियंताओं का भी जारी किया गया सिंगल - सिंगल आदेश,सिंचाई विभाग में एक नई प्रथा को विभागाध्यक्ष चला कर विभाग एवं सरकार की छवि को खराब करने में लगे हैं,सिंगल - सिंगल आदेश सिर्फ सिंचाई विभाग ही क्यों जारी कर रहा।

बढ़ता जा रहा केंद्र व राज्यों में टकराव!

» एडीए सरकार पर विपक्ष हमेशा कर रहा प्रहार

» भाजपा को कांग्रेस, सपा के साथ दक्षिण की पार्टियों ने भी घेरा

» भाषा, शिक्षा से लकर औरंगजेब तक पहुंची सियासी लड़ाई

» भाजपा ओड़िशा के विरासत को छेड़ रही : नवीन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आजकल केंद्र व राज्यों के बीच विवाद ज्यादा बढ़ गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण दोनों जगह भिन्न-भिन्न दलों की सरकारों का होना है। दिल्ली में बैठी एनडीए की मोदी सरकार व दक्षिणी राज्यों में आपसी मनमुटाव होना आम है। अब ओडिशा में भी बीजद वहां भाजपा सरकार में पंचायती राज दिवस व बीजू पटनायक के जन्मदिन को लेकर हंगामा मचा है। दक्षिण में सबसे ज्यादा बवाल हिंदी को लेकर है। खासतौर ये मुद्दा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी है।

कुल मिलाकर जहां आंध्र प्रदेश को छोड़ कर केरल, तमिलनाडु , कर्नाटक व तेलंगाना में केंद्र व राज्य टकराव होना बाजिब है क्योंकि इन राज्यों में क्रमश: वामदलों, द्रमुक व कांग्रेस की सरकारें है जिनकी विचारधार केंद्र की भाजपा की विचारधार से अलग है। आने वाले समय में ये विवाद चुनावी प्रचार के टूल्स भी बन सकत है। बीजद द्वारा ओडिशा की भाजपा सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की विरासत को मिटाने का प्रयास करने का आरोप लगाने के बीच विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने बुधवार को अपने पिता की 109वीं जयंती पर आयोजित राज्य सरकार के समारोह का बहिष्कार किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विपक्ष के नेता नवीन पटनायक को दिग्गज नेता बीजू पटनायक की जयंती पर बुधवार को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। माझी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर दोनों उपमुख्यमंत्री भी मौजूद थे। भुवनेश्वर से दो बीजद विधायकों – अनंत नारायण जेना और सुशांत कुमार राउत – और महापौर सुलोचना दास ने भी समारोह का बहिष्कार किया। हालांकि बीजद सरकार में वित्त मंत्री रहे प्रफुल्ल घदाई ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम को संबोधित किया। घदाई बीजू पटनायक के करीबी सहयोगी थे। माझी ने बीजद अध्यक्ष समेत सभी से बीजू पटनायक की जयंती जैसे शुभ दिन पर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया। बीजद अध्यक्ष ने कहा, तीन दशक से ओडिशा में बीजू बाबू के जन्मदिन के अवसर पर पांच मार्च को पंचायती राज दिवस मनाया जाता रहा है। लेकिन, भाजपा सरकार ने अब इस प्रथा को बंद कर दिया है और तारीख को 24 अप्रैल कर दिया है।

औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र यूपी व बिहार में बवाल

महाराष्ट्र में सपा नेता अबु आजमी द्वारा औरंगजेब की तारीफ के बाद विवाद हो गया । ये विवाद एक ही राज्य मे सीमित नहीं रह गया है। अब यह मामला महाराष्ट्र से यूपी होते हुए बिहार भी पहुंच गया है। यूपी सीएम योगी व सपा मुखिया के इस मामले में अपने-अपने विचार रख चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को गिरफ्तार किया जाएगा। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा विधायक को हिरासत में लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करते हुए दावा किया कि उसके शासन के दौरान भारत की सीमाएँ अफगानिस्तान और बर्मा (म्यांमार) तक फैली हुई थीं। इस बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है और महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। वहीं एक अन्य घटनाक्रम में, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने आजमी की विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की, और राज्य विधानसभा से उनके स्थायी

निलंबन की मांग की। उन्होंने कहा, उन्हें स्थायी रूप से निलंबित किया जाना चाहिए। यह सिर्फ बजट सत्र के लिए नहीं होना चाहिए, निलंबन स्थायी होना चाहिए। इससे पहले, मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली उनकी टिप्पणी पर सपा विधायक को बुधवार को 26 मार्च को चल रहे बजट सत्र के समाप्त होने तक महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। अन्याय का रोना रोते हुए आजमी ने कहा कि अपनी टिप्पणी वापस लेने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

जदयू नेता के बयान पर भाजपा भड़की

महाराष्ट्र के बाद चुनावी राज्य बिहार में भी औरंगजेब विवाद की एंट्री हो चुकी है। सपा विधायक अबू आजमी के बाद बिहार में जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने भी औरंगजेब के समर्थन में बयान दिया है जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि औरंगजेब को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है। इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और वह उतना क्रूर नहीं था जितना उसे दिखाया जाता है, एक लॉबी है जो उन्हें क्रूर दिखाने की कोशिश कर रही है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने कहा कि यह एक अकादमिक चर्चा है और इस पर संसद या राजनीतिक रैली में चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए, अकादमिक चर्चा को अकादमिक ही रहने दिया जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि एक राजनीतिक दल औरंगजेब के खिलाफ इस तरह की गलत सूचना से क्या हासिल करना चाहता है। एआईएमआईएम बिहार अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि नफरत की राजनीति से राजनीतिक लाभ उठाने के अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा काम नहीं है। औरंगजेब एक महान सम्राट थे। उन्होंने टोपियाँ सिलकर आजीविका अर्जित की। उन्होंने करदाताओं का पैसा अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें यहीं दफनाया गया था। वह अंग्रेजों की तरह लूटकर नहीं गये बल्कि उन्होंने इस देश की सेवा की। उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर बर्मा (म्यांमार) तक फैले भारत को एकीकृत किया और इसे अखंड भारत बनाया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि कउन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों के साथ समान व्यवहार किया। तो, ऐसा विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सरकारों पर स्वत:संज्ञान लेना चाहिए। अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई असंवैधानिक है।भाजपा ने इसको लेकर पलटवार किया है। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता नीरज कुमार सिंह बब्लू ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। औरंगजेब ने इस देश को लूटा। वह एक अत्याचारी के रूप में जाना जाता था। तो जिसने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। जो लोग उनके समर्थन में बोलते है वे देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में उनके पक्ष में चर्चा हो रही है तो यह बेहद दुखद और चिंताजनक है। जो लोग उनके पक्ष में बोलते हैं उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास से सीखना चाहिए और अगर हम देश को लूटने वालों का महिमामंडन करते हैं तो यह बहुत दुखद है।

उत्तरी राज्यों में तमिल पढ़ाने की व्यवस्था क्यों नहीं है : स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कथित तौर पर हिंदी थोपने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आश्चर्य जताया कि केंद्र सरकार ने उत्तर भारत के राज्यों के लोगों को तमिल या अन्य दक्षिण भारतीय भाषाएं सिखाने के लिए संस्थान स्थापित करने में मदद क्यों नहीं की। 'हिंदी थोपे जाने का विरोध' विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित पत्र में स्टालिन ने कहा कि 'गूगल ट्रांसलेट', 'चैट (जीपीटी)' और कृत्रिम मेधा (एआई) जैसी तकनीक लोगों को संबंधी समस्याओं से निपटने में मदद करती हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए केवल आवश्यक तकनीक सीखना फायदेमंद होगा। किसी को थोपना उन पर केवल बोझ होगा। द्रमुक प्रमुख ने कहा कि गांधीजी का मानना था कि दक्षिणी राज्यों के लोग हिंदी सीखें और उत्तरी राज्यों के लोग दक्षिणी भाषाओं में से एक सीखें, जिससे राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त होगा और राष्ट्रपिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी। स्टालिन ने कहा, ''गांधी जी ने खुद चेन्नई में सभा के मुख्यालय में कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था और वर्तमान में ये सभा छह हजार केंद्रों के साथ दक्षिणी राज्यों में काम कर रही है।'इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिए बगैर पूछा कि क्या उत्तर भारत में 'उत्तर भारत तमिल प्रचार सभा या द्रविड़ सभा' जैसा कोई संगठन स्थापित किया गया है, ताकि उत्तरी राज्यों के लोगों को दक्षिणी राज्यों की भाषाओं में से किसी एक को सीखने में सुविधा हो? मुख्यमंत्री ने भाजपा का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जिन लोगों ने गंगा नदी के तट पर संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थापित करने का दावा किया था, उन्होंने उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया।उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या ऐसे लोग तमिल का प्रचार करने के लिए कोई संस्था स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि 'जो लोग गोडसे के मार्ग पर चलते हैं, वे गांधी के उद्देश्यों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे।' दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जिसे 1964 में संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था, की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने दक्षिणी राज्यों में हिंदी का प्रचार करने के उद्देश्य से की थी और इसके पहले प्रचारक उनके पुत्र देवदास गांधी थे।

महाराष्ट्र में शुरू हुआ भाषा विवाद, सीएम फडणवीस ने संभाला मोर्चा

फडनवीस राज्य विधानसभा में शिवसेना (यूबीटी) के सदस्य भास्कर जाधव की मांग के जवाब में बोल रहे थे कि सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी की टिप्पणियों पर अपना रुख स्पष्ट करे कि मुंबई आने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि मराठी सीखे। महाराष्ट के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि मराठी मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा है और जो कोई भी यहां रहता है उसे इसे सीखना और बोलना चाहिए। फडनवीस राज्य विधानसभा में शिवसेना (यूबीटी) के सदस्य भास्कर जाधव की मांग के जवाब में बोल रहे थे कि सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी की टिप्पणियों पर अपना रुख स्पष्ट करे कि मुंबई आने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि मराठी सीखे। जोशी ने कहा था कि मुंबई में एक भाषा नहीं है। इसमें कई भाषाएं हैं। कुछ क्षेत्रों की अपनी भाषा है। घाटकोपर की भाषा गुजराती है। गिरगांव में, आपके पास हिंदी बोलने वाले कम और मराठी बोलने वाले अधिक होंगे। इसलिए यह आसान है कि मुंबई आने वाला कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं कि मराठी

सीखे। विधानसभा में जब जाधव ने इस पर सरकार से जवाब मांगा तो फड़णवीस ने कहा, %%मैंने नहीं सुना कि भैयाजी ने क्या कहा, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। उन्होंने कहा, हर किसी को मराठी सीखनी चाहिए और भाषा बोलनी चाहिए। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार अन्य भाषाओं का भी सम्मान करती है। फडणवीस ने कहा, यदि आप अपनी भाषा से प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो आप अन्य भाषाओं के साथ भी ऐसा ही करते हैं। मुझे यकीन है कि भैयाजी मुझसे सहमत होंगे। इससे पहले दिन में, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने दावा किया कि जोशी की टिप्पणी देशद्रोह के समान है और महाराष्ट्र का अपमान है। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने दावा किया, मराठी हमारी राज्य भाषा है और इस तरह का बयान देशद्रोह है। यह बयान देशद्रोह है। राज्यसभा सदस्य ने सीएम फड़नवीस और उनके डिप्टी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को जोशी के बयान की निंदा करने और इस मामले पर राज्य विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित करने की चुनौती दी। इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए राउत ने दावा किया कि जोशी मुंबई की नीतियां और लक्ष्य तय करते हैं। राज्यसभा सदस्य ने आगे दावा किया कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करते हुए जो कहा था, यह टिप्पणी उससे भी अधिक गंभीर थी।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर न हो अराजकता

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े मंचों के दुरुपयोग पर चिंता से सहमति जताते हुए भी सेंसरशिप और नॉर्म (मानदंड) के बीच के फर्क को रेखांकित किया। उसका कहना था कि सरकार को इस संबंध में गाइडलाइंस लानी चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी पर गैरजरूरी पाबंदियों का रूप न ले लें।

आज सोशल मीडिया जैसे मंचों के बेजा इस्तेमाल की प्रवृति बढ़ रही है। अभी हाल ही में कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसी आपत्तिजक सामग्रियां परोसी जिससे बवा लमच गया है। ये आपत्तिजक जनक चिजें वाकई भारत जैसे देश के लिए उचित नहीं है। हालांकि इसके लिए वे ही अकेले जिम्मेदार नहीं है । इसमे सरकारे व वह एजेंसियां भी शामिल हैं जिनकी जिम्मेदारी है वह इन पर नकेल कसे। कुल मिलाकर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उच्छृंखलता नामंजूर हो ना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब जैसे सोशल मंचों पर ऐसी सामग्री परोसी जा रही है, जो अशिष्ट, अभद्र, हिंसक, भ्रामक, राष्ट्र-विरोधी एवं समुदाय विशेष के लोगों को आहत करने वाली होती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को जोड़ना नहीं, तोड़ना है। इन सोशल मंचों पर ऐसे लोग सक्रिय हैं, जो तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास करते हैं, वे चरित्र-हनन और गाली-गलौच जैसी ओछी हरकतें करने के लिये उद्यत रहते हैं तथा उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक नीति अपनाते हुए अराजक माहौल बनाते हैं।

एक प्रगतिशील, सभ्य एवं शालीन समाज में इस तरह की हिंसा, अश्लीलता, नफरत और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडम्बना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चलते सरकार इन अराजक स्थितियों पर काबू नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े मंचों के दुरुपयोग पर चिंता से सहमति जताते हुए भी सेंसरशिप और नॉर्म (मानदंड) के बीच के फर्क को रेखांकित किया। उसका कहना था कि सरकार को इस संबंध में गाइडलाइंस लानी चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी पर गैरजरूरी पाबंदियों का रूप न ले लें। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह ऐसे समय सामने आया है जब देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विभिन्न समुदायों का विचलन, द्वेष एवं नफरत काफी बड़ी हुई दिख रही है। शासन प्रशासन की ओर से इन्हें रोकने की कोशिशों में भी अक्सर अति-उत्साह की झलक देखने को मिलती है। हालांकि सोशल मीडिया के ये मंच स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक भूमिका भी निभाते देखे जाते रहे हैं। उन पर क?ई से बहुत सारे ऐसे लोगों के अधिकार भी बाधित होने का खतरा है, जो स्वस्थ तरीके से अपने विचार रखते और कई विचारणीय मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। मगर जिस तरह ब?ी संख्या में वहां उपद्रवी, हिंसक, राष्ट्रीय और सामाजिक समरसता को छिन्न-भिन्न करने वाले तत्त्व सक्रिय हो गए हैं, उससे चिंता होना स्वाभाविक है। इससे जहां नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, वहीं इसके गलत इस्तेमाल की बेजा स्थितियां भी देखने को मिलती है। शीर्ष अदालत ने याद दिलाया है कि इस अधिकार का ख्याल रखा जाए।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

संसदीय सीटों के परिसीमन के यक्ष प्रश्न

प्रमोद जोशी

केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से देश के राजनेताओं और विश्लेषकों के एक तबके ने दो-तीन बातों पर जोर देना शुरू कर दिया है। वे कहते हैं कि भारत में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र विफल हो रहा है और यह भी कि लोकतंत्र का मतलब चुनाव जीतना भर नहीं होता। लोकतंत्र ही नहीं, संघवाद को भी खतरे में बताया जा रहा है। बीजेपी के हिंदू-राष्ट्रवाद की अतिशय केंद्रीय-सत्ता को लेकर भी उनकी आपत्तियां हैं। इधर तमिलनाडु से हिंदी-साम्राज्यवाद को लेकर बहस फिर से शुरू हुई है, जिसमें संसदीय-सीटों के परिसीमन को लेकर आपत्तियां भी शामिल हैं। दक्षिण के नेताओं का तर्क है कि यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा, तब दक्षिण के राज्य नुकसान में रहेंगे, जबकि जनसंख्या-नियंत्रण में उनका योगदान उत्तर के राज्यों से बेहतर रहा है। उनका सुझाव है कि संसदीय परिसीमन में संघवाद के मूल्यों का अनुपालन होना चाहिए।

परिसीमन से जुड़े इन्हीं सवालों को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 5 मार्च को चेन्नई में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा- तमिलनाडु अपने अधिकारों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। परिसीमन का खतरा दक्षिणी राज्यों पर डैमोक्लीज़ की तलवार की तरह मंडरा रहा है। मानव विकास सूचकांक में अग्रणी तमिलनाडु के सामने गंभीर खतरा खड़ा है। उनका यह भी कहना है कि अभी तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। परिसीमन की प्रक्रिया से इनकी संख्या घटकर 31 रह जाने की संभावना है। बात सिर्फ संख्या में कमी की नहीं है, यह हमारे अधिकारों का मामला है। स्टालिन के इस बयान के फौरन बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों को 'एक भी सीट' नहीं गंवानी पड़ेगी। उन्होंने तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की लंबे समय से चली आ रही इस आशंका को दूर करने का प्रयास किया कि यदि नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया गया तो संसद में उनका प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा।

हालांकि इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन करना होगा, पर आज जो बातें हो रही हैं, वे कयासों और अटकलों पर आधारित हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या और

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इसके विभाजन को फिर से समायोजित किया जाएगा। यह 'परिसीमन प्रक्रिया' संसद के एक अधिनियम के तहत गठित 'परिसीमन आयोग' द्वारा की जाती है। इस तरह की कवायद 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद की गई थी। इसमें इन सदनों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी शामिल है। वर्ष 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या 494, 522 और 543 तय की गई थी, जब जनसंख्या क्रमश: 36.1, 43.9 और 54.8 करोड़ थी। इसका मोटे तौर पर मतलब है कि प्रत्येक सीट पर औसतन क्रमश: 7.3, 8.4 और 10.1 लाख आबादी थी। जनसंख्या-नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए 1971 की जनगणना के बाद से इसे स्थिर रखा गया है ताकि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में सीटों की संख्या अधिक न हो। यह कार्य 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पहले वर्ष 2000 तक के लिए किया गया था। फिर 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक बढ़ा दिया गया था। अभी जिस जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या तय है, वह 1971 की जनगणना के अनुसार है। 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर इस संख्या को फिर से समायोजित किया जाएगा। अभी लगता नहीं कि 2026 के पहले वह जनगणना हो भी पाएगी या नहीं, जिसे 2021 में होना था। यह देखते हुए कि विधायिका में महिलाओं का आरक्षण भी जनगणना और परिसीमन से जुड़ा हुआ है, इसमें देरी दिक्कत पैदा करेगी। राज्यों में भी जनसंख्या वृद्धि में समतुल्यता के लिए सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के अनुरूप फ्रीज कर दिया गया है।

बहरहाल, पहले इस बात पर विचार करना होगा कि परिसीमन की नई प्रक्रिया में केवल राज्य की जनसंख्या का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा या नहीं। आनुपातिक संख्या पर नजर डालें, तो तमिलनाडु की यह चिंता जायज है। थोड़ी देर के लिए तमिलनाडु और अविभाजित बिहार की जनसंख्या की वृद्धि दरों (1971-2024) में अंतर देखा जा सकता है। मतदाताओं की संख्या के जो नवीनतम अनुमानित आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार अविभाजित बिहार में 233 फीसदी की वृद्धि हुई है।

ग्लेशियरों पर संकट के बीच हमारी जिम्मेदारी

वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा ग्राम के पास हुई हिमस्खलन की घटना में बीआरओ के मजदूर दब गए थे, जिनमें से कुछ को बचा लिया गया, लेकिन कई की जानें नहीं बच सकीं। दरअसल, हिमस्खलन की घटनाएं पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, जिससे अचानक बाढ़ें आ रही हैं और सड़कों पर वाहन सवार सैलानियों की मौतें हो रही हैं। फरवरी, 2021 में उत्तराखंड की नीती घाटी में हिमस्खलन के कारण ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में बाढ़ आई, जिससे व्यापक तबाही हुई। इस घटना के चलते वैश्विक स्तर पर हिमस्खलनों और ग्लेशियरों के संकट को लेकर चर्चा शुरू हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्लेशियरों के पिघलने की प्रक्रिया में मानवीय गतिविधियों का भी योगदान है, जिससे इन घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। ग्लेशियरों का पिघलना प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप जैसे जलविद्युत परियोजनाओं, निर्माण कार्यों और पर्यावरणीय असंतुलन ने इसे और बढ़ा दिया। इसलिये, हमें इन संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ से हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना दुगनी दर से बढ़ गया है। वे हर साल आधे मीटर की मोटाई खो रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में पीछे भी खिसक रहे हैं। गढ़वाल हिमालय में पिछले चार दशकों में औसतन 18 मीटर प्रति वर्ष ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने की दर तापमान, बारिश, नमी, हवाओं की गति और सूर्य की किरणों के परावर्तन पर निर्भर करती है। पिघलते ग्लेशियरों से उत्पन्न जल से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी सदानीरा नदियों का अस्तित्व है, जो वर्षा के बिना भी बहती रहती हैं। यदि ग्लेशियरों का पिघलना जारी रहता है, तो इससे समुद्र स्तर 230 फुट तक बढ़ सकता है, जो वैश्विक जल संकट का कारण बन सकता है।

नदियों में पानी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, गंगा और यमुना के स्रोतों, गंगोत्री और यमुनोत्री के ग्लेशियरों को नैनीताल उच्च न्यायालय ने 20 मार्च, 2017 को एक आदेश में न्यायिक जीवित मानव का दर्जा दिया। हालांकि ग्लेशियर स्वयं मौसमी बदलाव और बढ़ते तापमान से काल-कवलित हो रहे हैं, लेकिन इनकी सतह जब सूर्य की किरणों को परावर्तित करती है, तो वे वातावरण संतुलन में भी मदद करती हैं। छोटे ग्लेशियर्स औसतन 70 से 100 मीटर तक मोटे होते हैं, जबकि बड़े ग्लेशियर्स 1.5 किमी तक मोटे हो सकते हैं। गतिक ग्लेशियर्स अपनी यात्रा के दौरान शिलाओं को तोड़ते हुए उन्हें उनके मूल स्थानों से दूर ले जाते हैं, जिससे हिमस्खलन के दौरान हिमखंडों के साथ बड़ी-बड़ी शिलाओं की भी बौछार होती है। जब ये हिमखंड और शिलाएं नदियों-नालों में गिरती हैं, तो कभी-कभी बहते पानी की राह रोक अस्थायी बांध बना देती हैं। इन बांधों के टूटने से अचानक बाढ़ों और तबाही का खतरा उत्पन्न हो सकता है। हिमस्खलनों के अतिरिक्त, बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों में उत्पन्न होती और फैलती ग्लेशियल झीलें सर्वाधिक चिंता का कारण बन रही हैं। जिनके टूटने पर भारी मात्रा में पानी बहकर ये अचानक बाढ़ों का कारण बनती है, जिसे ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है।

ग्लेशियर्स प्राय: पहाड़ी निर्जन क्षेत्रों में होते हैं। अगर हम आर्थिक लाभ या मनोरंजन के लिए उनके नजदीक न जायें, तो शायद उनके टूटने या ग्लेशियर झीलों के अनायास टूटने का प्रभाव बस्तियों और संरचनाओं पर उतना भयंकर न होता। हालांकि, आज नंदादेवी बायोस्फीयर जैसे संरक्षित क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रोजेक्ट, जैसे जल विद्युत परियोजनाएं, स्कीइंग रिसॉर्ट्स और वेडिंग डेस्टिनेशन जैसी गतिविधियों को लेकर प्रवेश किया जा रहा है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद, जीएसआई ने 2014-16 में एक विशेष अध्ययन किया, जिसमें उत्तराखंड में 486 ग्लेशियल झीलों की पहचान की गई, जिनमें से 13 अत्यधिक जोखिमपूर्ण हैं। इन झीलों में से 71 ऋषिगंगा और धौलीगंगा घाटियों के ऊपर स्थित हैं, जो भूकंप, बादल फटने या भूगर्भीय कारणों से विखंडित हो सकती हैं। मानवीय कारणों से अब ग्लेशियरों से हिमखंड टूटने की घटनाओं का जोखिम बढ़ गया है। यदि हिमखंडों के गिरने या बहने के रास्ते के भूभागों को कमजोर किया गया, तो फ्लैश फ्लड की संभावना बढ़ सकती है।

ऐसे में, हमें ग्लेशियरों की अनदेखी करने की बजाय उनके संवेदनशील क्षेत्रों जैसे नंदादेवी बायोस्फीयर और गंगोत्री, केदारनाथ के आसपास के संरक्षित क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय असंतुलन से बचाने की नीति अपनानी चाहिए। ग्लेशियरों के नीचे पहाड़ी दरारों में पानी जमना और बर्फ का पिघलना भी एक सतत प्रक्रिया है, जो पहाड़ों को कमजोर करती है। इस प्रकार, ग्लेशियर अपने नीचे की चट्टानों को कमजोर करके उनका क्षरण करता रहता है, जिससे और भी अधिक खतरे पैदा हो सकते हैं। ग्लेशियरों के आधार के पहाड़ों में मशीनी कटान और विस्फोट स्थितियां और भी जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। यदि घाटियां संकरी हैं या वहां मलबा जमा है, तो फ्लैश फ्लड आ सकता है। एक वैज्ञानिक के अनुसार, यह आपदा ग्लेशियरों से जुड़ी भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे लैंड स्लाइड, ढलाव का टूटना, अत्यधिक तापमान आदि। ग्लेशियरों के लिए स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य को पुन: प्राप्त कर सकें।

अपनों को खिलाएं एप्पल गुझिया

होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग अपनी दुश्मनी भुला कर एक ही रंग में रंग जाते हैं। इस साल 13 मार्च को होली का ये त्योहार मनाया जाएगा। इस जश्न को मनाने के बाद लोग होली की बधाई देने के लिए एक-दूसरे के घर जाते हैं। इसी के चलते लोग अपने-अपने घरों में कई तरह के खाने के सामान बनाते हैं। होली के त्योहार में गुजिया एक ऐसी चीज है जो तकरीबन हर एक घर में मिल जाएगी। गुजिया बनाना वैसे तो ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, पर हर साल एक जैसी गुजिया खाकर लोग बोर होने लगे हैं। ऐसे में आप एक खास तरह की गुजिया बनाइए। जिसे खाकर लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। दरअसल, हम आपको एप्पल गुजिया के बारे में बात कर रहे हैं। जिसे बनाना काफी आसान है।

सामग्री

3 कप मैदा, 300 ग्राम खोया, 1/4 कप सूजी, 1/2 कप घी, 1.5 कप कसे हुए सेब, 2 चम्मच काजू, 20 किशिमिश, 300 ग्राम पाउडर शुगर, 2 चम्मच पिस्ता, 2 चम्मच बादाम, आधा चम्मच हरी इलायची।

विधि

एप्पल गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैदा में घी अच्छे से मिलाएं। इसके बाद अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए मैदा को गूंथ लें। मैदा को अच्छे से गूंथ कर इसे अलग ढक कर रख दें। अब एक कढ़ाई में खोया और सूजी को सुनहरा होन तक भूनें। इसे ठंडा होने के बाद इसमें हर तरीके के ड्राईफ्रूट डालें। इसके बाद अब एक पैन लें और इसमें कसे हुए सेब डालकर इसे सुखा लें। अब इसमें चीनी और खोया डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद आपकी स्टफिंग तैयार हैं। अब तैयार मैदा की छोटी-छोटी लोई बनाकर इसमें स्टफिंग डालें। इसे सांचे की मदद से फोल्ड करें। अब लास्ट में इसे केसर के धागों के सजाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं।

घर पर बनाएं मसाला पराठा

अक्सर ऐसा होता है कि हम हर रोज वही रोटी सब्जी खाते-खाते बोर हो जाते हैं। तो मसाला पराठा बनाएं। जिसे आप घर पर ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। भारतीय घरों में पराठा एक ऐसी डिश है जिसे लोग नाश्ते में बड़े चाव के खाते हैं। कभी आलू के पराठे तो कभी गोभी के, इतना ही नहीं पराठे तो पनीर के भी काफी लजीज लगते हैं। पर अगर इनसे भी मन भर जाए तो आप मसाला पराठा बना सकते हैं। ये खाने में जितना टेस्टी और अलग होगा उतना ही इसे बनाना आसान होता है। तो आप अगर रोज एक जैसा नाश्ता करते-करते बोर हो गए हैं और पराठे की वैराइटीज में भी कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो मसाला पराठा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

सामग्री

आटा- 1 कप, बेसन-1 कप, जीरा- 1/2 टी स्पून, अजवाइन- 1 टी स्पून, अदरक पेस्ट- 1 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर- 1 टी स्पून, हींग-1 चुटकी, कसूरी मेथी-1 टेबलस्पून, हरा धनिया कटा- 2 टेबलस्पून, तेल- जरूरत के मुताबिक, नमक- स्वादानुसार

विधि

मसाला पराठा बनाने के लिए एक बाउल में आटा और बेसन छान कर मिक्स करें। इसके बाद इसमें लाल मिर्च के साथ जीरा, अजवाइन, हींग, कसूरी मेथी, बारीक कटा हरा धनिया और स्वादानुसार नमक आटे के मिक्सर में मिला दें। पराठे को खस्ता बनाने के लिए इसमें एक चम्मच तेल डालें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से गूंथ लें।

अब इसे ढक कर आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद इसे एक बार फिर से अच्छे से गूंथ लें। अब इसकी लोइयां तैयार करके तवे को गर्म करने रख दें। इस के बाद लोइ का गोल या तिकोना पराठा बेल लें। अब तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर चारों ओर फैला दें। पराठे को सुनहरा होने तक सेकें। अब इसी तरह बाकी पराठे भी सेंक लें। इसे चाय के साथ हरी चटनी और केचअप के साथ सर्व करें।

हंसना मना है

5 साल का बच्चा- आई लव यू मां, मां- आई लव यू टू बेटा! 16 साल का लड़का - आई लव यू मॉम, मां- सॉरी बेटा, पैसे नही है! 25 साल का लड़का- आई लव यू मां, मां- कौन है वो चुड़ैल? कहां रहती है? 35 साल का आदमी- आई लव यू मां, मां- बेटा मैंने पहले ही बोला था, उस लड़की से शादी मत करना! और सबसे बढ़िया। 55 साल का आदमी- आई लव यू मां, मां- बेटा, मैं किसी भी कागज पर साइन नहीं करूंगी!

फ्रेंड- यार तुम्हारी दुकान मिठाई की है, तो क्या तुम्हारा दिल नहीं करता, मिठाई खाने को? संता- यार करता तो बहुत है, लेकिन पापा रसगुल्ले गिन के जाते है, तो। इसलिए, चूसकर रख देता हूं।

हम हमेशा दो लोगों के लिए अगरबत्ती लगाते है, एक भगवान के लिए, उन्हें बुलाने के लिए और दूसरी अगरबत्ती मच्छर के लिए, उन्हें भगाने के लिए। पर होता उसके बिलकुल उलटा है। भगवान आते नहीं है और मच्छर है कि जाते नहीं है।

कहानी — लड़ती बकरियां और सियार

बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में किसी बात को लेकर दो बकरियों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े को वहां से गुजर रहा एक साधु देख रहा था। देखते ही देखते दो बकरियों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में लड़ने लगीं। उसी समय वहां से एक सियार भी गुजरा। वह बहुत भूखा था। जब उसने दोनों बकरियों को झगड़ते देखा, तो उसके मुंह में पानी आ गया। बकरियों की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ने एक-दूसरे को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन फिर भी लड़ना नहीं छोड़ रही थीं। दोनों बकरियों के शरीर खून निकलने लगा था। भूखे सियार ने जब जमीन पर फैले खून की तरफ देखा, तो उसे चाटने लगा और धीरे-धीरे उनके करीब जाने लगा। उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई थी। उसके मन में आया कि क्यों न दोनों बकरियों को मारकर अपनी भूख मिटाई जाए। वहीं, दूर खड़ा साधु यह सब देख रहा था। जब उसने सियार को दोनों बकरियों के बीच जाते हुए देखा, तो सोचा कि अगर सियार इन दोनों बकरियों के और करीब गया, तो उसे चोट लग सकती है। यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है। साधु अभी यह सोच ही रहा था कि सियार दोनों बकरियों के बीच पहुंच गया। बकरियों ने जैसे ही उसे अपने पास आते देखा, तो दोनों ने लड़ना छोड़कर उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से सियार अपने आप को संभाल नहीं सका और चोटिल हो गया। वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। सियार को भागता देख बकरियां ने भी लड़ना छोड़ दिया और अपने घर लौट गईं। वहीं, साधु भी अपने घर की ओर चल दिया।

कहानी से सीख- हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों की लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए, इससे हमारा ही नुकसान होता है।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष — आज प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी। धनार्जन होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। प्रमाद न करें। भाइयों की मदद मिलेगी।

वृषभ — संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। बेरोजगारी दूर होगी। धन की आवक बनी रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य न करें। लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी।

मिथुन — रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। संतान के कार्यों पर नजर रखें। पूंजी निवेश बढ़ेगा।

कर्क — आज घर में क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दुःखद समाचार मिल सकता है। चिंता बनी रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में सावधानी रखें। वास्तविकता को महत्व दें।

सिंह — मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु शांत रहेंगे। धनार्जन होगा। आज विशेष लाभ होने की संभावना है। सगे-संबंधी मिलेंगे।

कन्या — मेहमानों का आवागमन होगा। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। मान बढ़ेगा। प्रसन्नता रहेगी। जल्दबाजी न करें। जोखिम के कार्यों से दूर रहें। पराक्रम में वृद्धि होगी।

तुला — यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल लाभ देंगे। भेंट आदि की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी। व्यापार में उन्नति के योग हैं।

वृश्चिक — वाणी पर नियंत्रण रखें। अप्रत्याशित बड़े खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है, जोखिम न लें। अजनबी व्यक्ति पर विश्वास न करें। विवादों से दूर रहना चाहिए।

धनु — नई योजना बनेगी। नए अनुबंध होंगे। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है। परिवार की समस्याओं की चिंता रहेगी।

मकर — नए अनुबंधों का लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। पूछ-परख रहेगी। रुके कार्य बनेंगे। जोखिम न लें। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। खानपान पर नियंत्रण रखें।

कुम्भ — कोर्ट व कचहरी के काम निबटेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। तंत्र-मंत्र में रुचि रहेगी। धनार्जन होगा। प्रमाद न करें। संतान के कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मीन — वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। दूसरों की जमानत न लें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है।

बॉलीवुड | मन की बात

बॉलीवुड इंडस्ट्री टॉक्सिक हो चुकी है, इसलिए मैंने मुंबई छोड़ा : अनुराग कश्यप

अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड में लीक से हटकर फिल्में बनाई हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से वह बॉलीवुड के वर्क कल्चर को लेकर काफी परेशान नजर आए। इसलिए निर्देशक ने मुंबई छोड़ने का मन बनाया। वह अब मुंबई से दूर दक्षिण भारत में जाकर बस गए। हाल ही में अनुराग कश्यप ने फिर से बॉलीवुड के खराब वर्क कल्चर को लेकर बात की।

द हिंदू से हालिया बातचीत में अनुराग कश्यप ने बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री टॉक्सिक हो चुकी है, इसलिए उन्होंने मुंबई छोड़ा। वह ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं। अनुराग का यह भी कहना है कि बॉलीवुड में हर कोई 800 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली फिल्म का टारगेट बनाकर चल रहा है, उस टारगेट का पीछा कर रहा है। इससे क्रिएटिव माहौल खत्म हो गया है। अनुराग से जुड़े करीबी सूत्रों का कहना है कि निर्देशक अब बेंगलुरु में शिफ्ट हो चुके हैं। आगे बातचीत में अनुराग कश्यप ने यह भी बताया कि वह मलायलम और तमिल फिल्म में फ्यूचर बनाना चाहते हैं। अनुराग ने बतौर अभिनेता कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया है, अधिकतर फिल्मों में वह नेगेटिव रोल में नजर आए। पिछले दिनों भी एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड एक्टर्स के बिहेवियर पर भी बात की है। वह इंटरव्यू में कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में हर एक्टर को स्टार ट्रीटमेंट चाहिए। जबकि साउथ इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, बड़े से बड़ा एक्टर फिल्म के बाकी लोगों की तरह ही खुद को ट्रीट करता है।

कियारा ने डॉन-3 से किया किनारा

बॉलीवुड | मसाला

कियारा आडवाणी की जिंदगी इस समय खुशियों से भरी हुई है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर मीडिया और फैंस के साथ साझा की। वह इन दिनों फिल्मों 'टॉक्सिक' और 'वॉर 2' की शूटिंग भी कर रही हैं। लेकिन इंडिया टुडे के अनुसार कियारा एक बड़ी फ्रैंचाइजी फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। वह इस फिल्म से खुद को अलग कर चुकी हैं।

फिल्म 'डॉन 3' से कियारा आडवाणी ने खुद को अलग कर लिया है। इस फिल्म को फरहान अख्तर बना रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में होंगे। इंडस्ट्री से जुड़े सोर्स का कहना है कि कियारा आडवाणी अपनी प्रेग्नेंसी पर फोकस करना चाहती हैं। पति और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी इन दिनों कियारा का काफी ध्यान रख रहे हैं। कियारा आडवाणी ने फिल्म 'डॉन 3' को छोड़ दिया है तो इसके मेकर्स अब नई हीरोइन की तलाश में लग चुके हैं। कियारा की जगह किस हीरोइन को फिल्म में रणवीर सिंह के अपोजिट लिया जाएगा, यह कुछ दिनों में पता चल जाएगा। इस फिल्म में विक्रांत मैसी भी एक अहम रोल निभा रहे हैं।

'डॉन' सीरीज की फिल्में दर्शकों को काफी पसंद हैं। डॉन सीरीज की फिल्मों की बात की जाए तो पहले दो हिस्सों में शाहरुख खान ने डॉन का रोल निभाया था। अब 'डॉन 3' में रणवीर सिंह डॉन के किरदार में नजर आएंगे। वैसे रणवीर सिंह इस वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुए थे कि वे शाहरुख की तरह डॉन के किरदार को शायद ही निभा पाएं।

फिल्म दे दे प्यार दे 2 को लेकर खुश हैं रकुल प्रीत

बॉलीवुड | मसाला

रकुल प्रीत सिंह शादी के बाद से लगातार हिंदी फिल्मों में काम कर रही हैं। अब उन्होंने अपनी नई फिल्म दे दे प्यार दे 2 के पटियाला शेड्यूल के खत्म होने की खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की है और साथ ही एक खास नोट भी लिखा है।

रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म दे दे प्यार दे 2 को लेकर अपनी खुशी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर करते हुए एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके साथ क्रू के कई लोग नजर आ रहे हैं। इस खास तस्वीर के साथ रकुल ने लिखा, इसके साथ ही हमने DDPD2 का पटियाला शेड्यूल पूरा कर लिया है। यह महीना बहुत अच्छा और संतोष देने वाला रहा। हां, ठंड बहुत थी और काम भी खूब था, लेकिन मेरी टीम ने मेरी मदद की और सब आसानी से हो गया। मैं चाहती हूं कि आप सब फिल्म देखें और उम्मीद है कि आपको आयशा का किरदार फिर से पसंद आएगा।

फिल्म दे दे प्यार दे 2 साल 2019 में आई दे दे प्यार दे की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का पहला पार्ट काफी सफल रहा था। वहीं अब दे दे प्यार दे के प्रशंसकों को इसकी दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इसका निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। दे दे प्यार दे 2 में रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। पहली फिल्म को बहुत पसंद किया गया था, इसलिए फैंस को इस सीक्वल का बेसब्री से इंतजार है। 'दे दे प्यार दे 2' में रकुल प्रीत 'आयशा' की अपनी भूमिका को दोहराती नजर आएंगी। अंशुल शर्मा के निर्देशन में तैयार सीक्वल में आर. माधवन भी हैं। हालांकि, अजय देवगन भी अपनी भूमिका को निभाते नजर आएंगे।

अजब-गजब | ये है भारत का सबसे ईमानदार गांव

इस गांव में नहीं होती चोरी, बिना दुकानदार खुली रहती हैं दुकानें

आज के समय में जहां दुनिया में चोरी-चकारी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, पुलिस का पूरा समय अपराधियों को पकड़ने में ही बीत रहा है, वहां एक ऐसा गांव है, जहां आजतक एक भी चोरी नहीं हुई है। अगर आपको लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं है। ये अनोखा गांव कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागालैंड के खोनोमा गांव की।

खोनोमा गांव को भारत का पहला ग्रीन विलेज कहा जाता है। इस गांव का इतिहास सात सौ साल पुराना है और यहां अंगामी जनजाति के लोग रहते हैं। इन आदिवासियों ने भारत की स्वतंत्रता में भी अहम योगदान दिया है। इसके अलावा अपने गांव को बचाने के लिए उन्होंने खुद से ही कई नियम बनाए, जिसे आज भी माना जाता है। इसमें जंगल के पेड़ ना काटना और शिकार पर प्रतिबंध शामिल है। लेकिन इनके अलावा ये गांव एक अन्य कारण से भी जाना जाता है। दरअसल, इस गांव को दुनिया का सबसे ईमानदार गांव कहा जाता है। कारण है कि आजतक इस गांव में एक भी चोरी नहीं हुई है।

इस गांव में आपको कई दुकान नजर आ जायेंगे।

यहां लोगों को अपनी जरुरत की सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन यहां आपको कोई दुकानदार नजर नहीं आएगा। जी हां, यहां दुकानों में सामान लेने के बाद रखे गए बॉक्स में लोग खुद से ही पैसे रख देते हैं। आजतक यहां चोरी की एक भी घटना नहीं हुई है। ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घर में ताला भी नहीं लगाते हैं।

इस गांव को भारत का पहला ग्रीन विलेज कहा जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, गांव में कुल 424 परिवार रहते हैं, जो बहादुरी और मार्शल आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। पहले जहां इस गांव में शिकार किया जाता था लेकिन 1998 में लोगों ने खुद ही इसपर प्रतिबंध लगा दिया। यहां पेड़ों की कटाई भी नहीं की जाती है। अगर किसी को कुछ बनवाना है तो वो सिर्फ पेड़ों की टहनियां काट लेते हैं। ये गांव भारत के अन्य गांवों के लिए मिसाल बना हुआ है।

इस छोटे से जीव से डरता है किंग कोबरा भिड़ जाय तो सांप को तड़पाकर देता है मौत

जब सांपों की बात आती है तो किंग कोबरा दुनिया का सबसे बड़ा विषैला सांप है। आमतौर पर ये सांप 13 फीट तक लंबा होता है। कोबरा का वैज्ञानिक नाम ओफियोफैगस है और इसकी खासियत ये है कि कोबरा दूसरे सांपों को भी खा सकता है। इतने खतरनाक सांप से जुड़ी हुई कई दिलचस्प बातें हैं लेकिन उनमें से एक ये है कि ज़हरीला होने के बाद भी ये सांप एक जीव से डरता है।

आमतौर पर तो किंग कोबरा ऐसा सांप है, जिसके नाम से ही हमारा दिमाग भन्ना जाता है। इसके ज़हर के आगे बड़े-बड़े जीव भी नहीं टिक पाते। हालांकि एक जीव ऐसा है, जिससे भिड़ने में किंग कोबरा भी घबराता है। किंग कोबरा का विष इतना शक्तिशाली होता है कि वह हाथी को भी मार सकता है, लेकिन हाथी के सामने पिद्दी से दिखने वाले इस जीव से कोबरा घबरा जाता है।

किंग कोबरा जैसे ज़हरीले सांप से जो बिल्कुल नहीं डरता, वो जीव नेवला या केरिया है। सांप और नेवले के बीच की दुश्मनी हमारे देश की लोक कथाओं में भी सुनी जा सकती है। जब भी किंग कोबरा के साथ सीधे टकराव की संभावना बनती है, किंग कोबरा इससे बचता है। हालांकि किंग कोबरा केवल 36 से 45 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका वजन 90 ग्राम से 1.7 किलोग्राम तक होता है, लेकिन नेवले के लिए ये सब मायने नहीं रखता क्योंकि सांप उनके लिए एक शिकार हैं। उनके ऊपर इनके ज़हर का भी असर नहीं होता। नेवले के बच्चों को तो सांप खा लेता है लेकिन जब वयस्क नेवलों की बात आती है, तो वे सांप को धूल चटा देते हैं। दरअसल नेवलों के शरीर में एसिटाइलकोलिन होता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो उनके दिमाग में मौजूद होता है। ये खून में मिले विष के न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट को कम कर देता है। इस वजह से नेवलों की सांप के जहर से मौत नहीं होती। वो जहर के प्रति इम्यून होते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। कभी-कभी सांप भी नेवले पर भारी पड़ जाते हैं लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता।

जितना बड़ा बजट होगा उतना होगा कर्ज : पटवारी

» बजट सत्र पर कांग्रेस ने मप्र सरकार को घेरा

» सरकार अपनी पांच उपलब्धियां बताए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। इससे पहले कांग्रेस सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। सत्र शुरू होने से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बजट को लेकर कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को मर्यादा की नहीं मानती। बजट सत्र 40 दिन दिन तक चलता है, लेकिन बीजेपी ने इसे 9 दिन का कर दिया।

जीतू पटवारी ने आगे कहा कि सरकार खुद के विधायक को 15 करोड़ और विपक्ष के विधायकों को जीरो रुपये देती है। बीजेपी वाले जनता का विरोध करते हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका विकास नहीं होगा। सरकार जितना बड़ा बजट लाएंगी, उतना कर्ज होगा। कर्ज लो, बजट बनाओ, कमीशन हम कमाओ और सौरभ शर्मा बनाओ ये काम सरकार का है। विधायकों से विधानसभा में सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाने को लेकर पटवारी ने कहा कि मैं सरकार से सवाल करता हूं कि सरकार अपनी पांच उपलब्धियां बता दे, मैं सीएम का नागरिक अभिनंदन करूंगा अगर आप पांच नहीं बता पाएं, तो मैं 500 नाकामियां बता दूंगा। बीजेपी की सरकार में महिलाओं, किसान, गरीब, सबको छला गया है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। पुलिस वाले रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। अगर पुलिस वाले वसूली ना करे तो अगले दिन वो सस्पेंड हो जाता है। हमारे प्रदेश में गृह विभाग छुट्टी पर है। ये सरकार नहीं सर्कस चल रहा है।

प्रदेश में चल रहा है गुंडा राज : देसाई

गोहद विधायक केशव देसाई को जान से मारने की धमकी पर जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, और हमारे एक विधायक को अस्पताल संचालक जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले को हम विधानसभा सत्र में उठाएंगे। एपल हॉस्पिटल संचालक अमित यादव और उनके भाई अंकित यादव पर जान से मारने का इल्जाम है। गोहद से कांग्रेस विधायक केशव देसाई ने विधानसभा में अस्पताल के घोटालों पर प्रश्न उठाने को कहा था, यह मामला मुख्यमंत्री और कांग्रेस हाई कमान तक पहुंच चुका है।

हिमानी की हत्या ने झकझोरा, अन्याय कब तक सहेंगे : विनेश फोगाट

रोहतक में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या करने पर अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी और जुलाना विधायक विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड ने झकझोर दिया है। विनेश ने हत्याकांड पर सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं पर अपराध रोकने में सक्षम नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार महिलाओं पर हो रहे अपराधों को रोकने में असमर्थ है। उन्होंने लिखा कि महिलाओं के खिलाफ यह अन्याय कब तक जारी रहेगा। रोहतक में हुई महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद परिजनों ने भी मीडिया के सामने आकर कांग्रेस नेताओं पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया था। इसको लेकर परिजनों ने दुख भी जताया था कि कांग्रेस नेता उनका इस मामले में सहयोग नहीं कर रहे। अब इस मामले में विधायक विनेश फोगाट ने पोस्ट कर दुख जताया।

बिहार में बजट को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल

» बड़ी गड़बड़ी हुई, ईओयू से जांच कराएं : सुधाकर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी के सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार हमला बोला है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पेश किए गए बजट में गड़बड़ी की गई है। बजट में 25 करोड़ रुपये पर्यावरण विभाग को दिया गया है। इसे बिहार ग्रीन डेवलमेंट कंपनी फंड नाम दिया गया है।

सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध इकाई से करवाए। सुधाकर सिंह ने बिहार विधानसभा में इसपर कोई बात नहीं कही, बाद में प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी ओर से सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ लोगों को फायदा देने के लिए योजना ला रही है और राशि खर्च करने का बजट दिखा रही है। उन्होंने कहा कि बजट में जो जरूरी था, वह नहीं लाया गया। राजद इस मुद्दे पर आक्रामक रूख अपनाएगी।

तेजस्वी में परिपक्वता की कमी : मांझी

बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स के बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। गया में मीडिया से बात करते हुए मांझी ने कहा कि राजनीति में जितना उम्रदराज होते हैं, उतना ही परिपक्वता आती है। तेजस्वी यादव द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बूढ़ा नेता नहीं चाहिए कहकर हमला करने पर मांझी ने कहा कि राजनीति में युवा होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ युवा होने से कुछ नहीं होता, उसमें अनुभव भी होना चाहिए। अगर तेजस्वी खुद को युवा समझकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें अभी परिपक्वता की कमी है। एनडीए में कई युवा नेता हैं, लेकिन महागठबंधन में सिर्फ तेजस्वी को ही युवा माना जाता है। सत्ता पाने के लिए महागठबंधन के नेता सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार देश और समाज के विकास के लिए समर्पित हैं।

महाराष्ट्र में एक और लड़की के साथ रेप

» मुंबई के घाटकोपर इलाके की घटना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार, नाबालिग की उम्र 12 से 15 साल के बीच की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया और दो अन्य लोगों ने उसे परेशान किया। जोगेश्वरी पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, जोगेश्वरी ईस्ट में रहने वाली नाबालिग लड़की घर में झगड़े के बाद नाराज होकर स्टेशन चली गई थी। वहां उसे कुछ परिचित लोग मिले, जो उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गए। वहां 26 फरवरी की रात तीन युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

मरीन ड्राइव में छेड़छाड़

घाटकोपर में दो अन्य युवकों ने उसे झांसे में लिया और पहले मरीन ड्राइव, फिर दादर ले गए। नाबालिग पीड़िता के बयान के अनुसार, इन दोनों ने उसके साथ छेड़खानी और बदसलूकी की। इस बीच, लड़की के परिवार ने जोगेश्वरी पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू की और आखिर में वो दादर स्टेशन में मिली। पुलिस ने दादर में मौजूद दोनों युवकों को गिरफ्तार किया, जो उसके साथ बदसलूकी कर रहे थे। इसके बाद पीड़िता के बयान के आधार पर गैंगरेप के तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

छात्रों की कब्रगाह बनता जा रहा है कोटा

» एक और छात्र ने लगाया मौत को गले मिला सुसाइड नोट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोटा। राजस्थान कोटा में दिन ब दिन आत्महत्या करने वालों की तदाद बढ़ती जा रही है। इस बीच कोटा से एक और सुसाइड का मामला सामने आया है। राजस्थान के कोटा में मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्र ने सुसाइड कर ली। वह पिछले तीन सालों से कोटा में रह रहा था। उसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। महावीर नगर एएसआई मोहन लाल ने इसकी जानकारी दी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है।

पुलिस को मृतक के कमरे से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि वह माता-पिता का सपना पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए उनसे माफी मांग रहा है। महावीर नगर सीआई रमेश कविया के अनुसार, बस्सी का रहने वाला 28 साल का सुनील बैरवा कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा था। उसने खुद को कमरे में बंद कर कर फांसी लगा ली। जब वह दिखाई नहीं दिया तो रात को उसके साथ हॉस्टल में रहने वाले लड़कों ने उसके कमरे में देखा तो वह फंदे पर लटका मिला। महावीर नगर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया।

11 फरवरी को भी हुआ था सुसाइड

मिली जानकारी के अनुसार इस साल कोटा में सुसाइड करने वाले छात्रों का यह 8वां केस है। इससे पहले 11 फरवरी को कोटा में नीट स्टूडेंट ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। छात्र का नाम अंकुश मीना था बताया गया था 18 साल की छात्र ने सुबह फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है।

यूपी वारियर्स की प्लेऑफ की उम्मीद खत्म

» महिला प्रीमियर लीग : अमेलिया केर के पांच विकेट और मैथ्यूज के आलराउंड प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस जीता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। पूर्व चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अमेलिया केर (पांच विकेट) की शानदार गेंदबाजी और हेली मैथ्यूज (68 रन, दो विकेट) के हरफनमौला प्रदर्शन से महिला प्रीमियर लीग के मैच में यूपी वारियर्स को नौ गेंद रहते छह विकेट से पराजित कर उसकी प्लेऑफ की उम्मीद खत्म कर दी।

मुंबई इंडियंस ने इस जीत से अपने नेट रन रेट में इजाफा किया और वह आठ अंक लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई। वह शीर्ष पर काबिज दिल्ली कैपिटल्स से दो अंक पीछे है और उसका एक मैच भी बचा है। उसके पास शीर्ष पर पहुंचकर फाइनल में सीधे जगह बनाने का मौका है। डब्ल्यूपीएल में शीर्ष टीम सीधे फाइनल में पहुंचती है जबकि दूसरे और तीसरे स्थान की टीम एलिमिनेटर खेलती हैं। यह यूपी वारियर्स की लगातार तीसरी हार थी जिससे वह चार अंक लेकर निचले स्थान पर बरकरार है। मैथ्यूज ने इस सत्र में अपनी दूसरी अर्धशतकीय पारी के लिए 46 गेंद का सामना करते हुए अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के जड़े, गेंदबाजी करते हुए दो विकेट भी लिए।

जॉर्जिया वॉल के अर्धशतक से शानदार शुरूआत

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल (55 रन) के अर्धशतक से शानदार शुरूआत करने वाली यूपी वारियर्स केर (38 रन देकर पांच विकेट) की शानदार गेंदबाजी के सामने नौ विकेट पर 150 रन ही बना सकी और मुंबई इंडियंस ने 18.3 ओवर में चार विकेट पर 153 रन बनाकर आसान जीत हासिल की। मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने केर की शानदार गेंदबाजी के बाद उन्हें इस सत्र में पहली बार पारी के आगाज के लिए भेजा था लेकिन वह 10 रन बनाकर आउट हो गईं और इस मौके का फायदा नहीं उठा सकीं। नैट साइवर ब्रंट (37 रन, 23 गेंद, सात चौके) ने मैथ्यूज का अच्छा साथ निभाया और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 58 गेंद में 92 की साझेदारी निभाकर जीत की नींव रखी।

ब्रंट के डब्ल्यूपीएल में 800 रन

नैट साइवर ब्रंट ने इस दौरान डब्ल्यूपीएल में 800 रन भी पूरे किए और वह ऐसा करने वाली चौथी बल्लेबाज बनी। इससे पहले यूपी वारियर्स ने जॉर्जिया (33 गेंद,12 चौके) और सलामी बल्लेबाज ग्रेस हैरिस (28 रन, तीन चौके, एक छक्का) के बीच पहले विकेट के लिए 7.5 ओवर में 74 रन की भागीदारी से अच्छी शुरूआत की। पर लगातार अंतराल पर विकेट गंवाने से उसके लिए फिर कोई बड़ी साझेदारी नहीं बन सकी। अपना दूसरा ही डब्ल्यूपीएल मैच खेल रही जॉर्जिया ने केर पर लगातार तीन चौके जड़ डाले। हेली मैथ्यूज ने हैरिस को आउट करके नियमित अंतराल पर विकेट लेने की शुरूआत की।

जम्मू-कश्मीर : फिर उठा राज्य दर्जा बहाली का मुद्दा

» बजट सत्र में विपक्ष ने उठाई मांग कांग्रेस ने सदन की समिति बनाने का दिया सुझाव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दूसरे दिन विधायकों ने सिंधु जल संधि, सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरना, आरक्षण नीति को युक्तिसंगत बनाने और विद्युत परियोजनाओं की वापसी से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात कही।

कांग्रेस विधायक ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को मजबूत करने के लिए सदन के सदस्यों की समिति बनाने की मांग की। भाजपा ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए बदलाव के साथ-साथ बजट तैयार करने से पहले सभी हितधारकों व विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक को सराहा। नेकां विधायकों ने राज्य के दर्जा की बहाली और सिंधु जल संधि से प्रदेश की बिजली उत्पादन की क्षमता पर पड़ रहा असर पर अपनी बात कही।

बहाली के लिए बने सदन के सदस्यों की समिति

कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि, हमें राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए मजबूत पहल करनी होगी। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल या सदन का एक पैनल नामित करना होगा जो केंद्र सरकार के समक्ष मामला पेश करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य है कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करे और संसद में किए गए अपने वादों का सम्मान करे।

सिंधु जल संधि से बिजली उत्पादन की क्षमता पर पड़ रहा असर

नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉ. बशीर अहमद वीरी ने उमर अब्दुल्ला सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ की क्षेत्रों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के सभी वर्गों के साथ बैठकें हुईं। वीरी ने सिंधु जल संधि के जम्मू-कश्मीर को बिजली उत्पादन के लिए पानी की पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। उन्होंने सरकारी विभागों में सभी रिक्तियों को भरने के मुद्दे पर भी चर्चा की। नेकां नेता गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने जम्मू-कश्मीर में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत पर जोर दिया। नेकां विधायक जावेद रियाज ने कहा कि हमें राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सामूहिक रूप से काम करना चाहिए।

मुगलों का इतिहास खत्म करने की हो रही कोशिश : फारूक अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश सरकार पर मुगलों का इतिहास मिटाने का आरोप लगाया। भाजपा पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला ने कहा वे मुगलों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। वे (मुगल) सैकड़ों वर्षों तक यहां रहे और यहीं दफन भी हुए। नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख मुगल बादशाह औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी विधायक की टिप्पणी और शहरों तथा ऐतिहासिक इमारतों के नाम बदलने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से उपजे विवाद पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

हमें सीएम के इरादों पर संदेह नहीं

सलाथियाबजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से सभी हितधारकों और विधायकों के साथ परामर्श को सत्ता पक्ष के अलावा मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी सराहा। भाजपा विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा कि पहली बार बजट तैयार करने के लिए जिला स्तर पर परामर्श किया गया।इसमें हितधारकों के साथ-साथ विधायकों को शामिल किया। हमें सीएम उमर के इरादों पर संदेह नहीं है। सरकार अभी अपने शुरुआती दौर में है, इसलिए उम्मीद है कि उमर लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। भाजपा विधायक राजीव जसरोटिया ने कहा कि इतिहास में पहली बार बजट-पूर्व परामर्श आयोजित किया गया। उन्होंने सरकार को घोषणापत्र में किए गए वादों की भी याद दिलाई। घोषणापत्र से गायब मुद्दों को उजागर किया।

तमिलनाडू में ईडी की छापेमारी मंत्री का घर भी शामिल

» एक साथ 10 जगहों पर हो रही है ईडी की कार्रवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु में धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 10 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई के तहत राज्य के आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके समर्थकों के घरों पर भी छापेमारी की गई है। सूत्रों के अनुसार, ईडी के 10 से अधिक अधिकारियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ मिलकर छापेमारी की।

इनमें प्रमुख रूप से करूर जिले के रायनूर स्थित कोंगू मेस के मालिक मणि (जिन्हें सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है) का घर शामिल है। इसके अलावा, इरोड रोड पर सरकारी ठेकेदार एम. शंकर आनंद और शक्ति मेस के मालिक कार्थी के आवासों पर भी छापेमारी की जा रही है। ये सभी लोग मंत्री सेंथिल बालाजी के समर्थकों के रूप में पहचाने जाते हैं। ईडी की यह छापेमारी धन शोधन के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, ईडी के अधिकारी इस कार्रवाई के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रहे हैं।

मंत्री सेंथिल बालाजी पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें वित्तीय धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे मामले शामिल हैं। ईडी इन आरोपों की गहन जांच कर रहा है, और इससे संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया जा सकता है, जो कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ईडी ने 'अवैध' विदेशी धनप्रेषण मामले में कई राज्यों में छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुखौटा कंपनियों के जरिए भारत से विदेशों में कथित तौर पर करोड़ों रुपये अवैध तरीके से भेजे जाने से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत शुक्रवार को कई राज्यों में छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह मामला राजस्थान के जयपुर में काम करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग की शिकायत से जुड़ा है। सूत्रों ने बताया कि छापे जयपुर, उदयपुर और अजमेर, मुंबई, सूरत और नोएडा में मारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुखौटा या फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये के कथित अवैध धनप्रेषण की जांच के तहत कुछ कारोबारियों और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

शाह और स्टालिन में तेज हुआ वार-पलटवार

तमिलनाडु के सीएम के बयान पर घमासान, बोले मुख्यमंत्री- एलकेजी स्टूडेंट पीएचडी होल्डर को लेक्चर नहीं दे सकता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने-सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार तमिलनाडु के कई दल और राजनेता केंद्र सरकार पर नेशनल एजूकेशन पॉलिसी के जरिए तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य करने और तमिल भाषा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं।

खुद तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन इस मुद्दे पर आर या पार का मुड़ बना चुके हैं। वह कई सार्वजनिक मंचों से हिंदी का विरोध जता चुके हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्र के शिक्षा नीति और तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम की तुलना करते हुए यह तक कह दिया था कि एलकेजी स्टूडेंट पीएचडी होल्डर को लेक्चर नहीं दे सकता। स्टालिन के इसी रवैये पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है।

अमित शाह ने दावा किया कि एमके स्टालिन ने तमिल भाषा के विकास के संबंध में पर्याप्त काम नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए अपनी भर्ती नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए है।

तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम शुरू करवाएं सीएम : शाह

शाह ने कहा, अभी तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) भर्ती में मातृभाषा के लिए कोई जगह नहीं थी। पीएम मोदी ने फैसला किया है कि हमारे युवा अब तमिल सहित आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में सीएपीएफ परीक्षा दे सकेंगे। मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वे जल्द से जल्द तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में कदम उठाए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हमें पत्र लिखने के लिए उकसाया : स्टालिन

स्टालिन ने केंद्र सरकार पर नेशनल एजूकेशन पॉलिसीके माध्यम से हिंदी थोपने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा के प्रयासों को तमिलनाडु की भाषाई पहचान यानी तमिल के लिए खतरा बताया। स्टालिन ने कहा, हम अपना काम कर रहे थे लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हमें पत्र लिखने के लिए उकसाया। उन्होंने पूरे राज्य को हिंदी थोपने के लिए धमकाया। अब उन्हें एक ऐसी लड़ाई को फिर से शुरू करने के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, जिसे वह कभी नहीं जीत सकते।

बरकरार रहेगी केजरीवाल की जेड प्लस सुरक्षा

» गृह मंत्रालय ने सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया फैसला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब में हैं। अरविंद केजरीवाल पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पंजाब के होशियारपुर में हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा में कटौती नहीं होगी। पूर्व सीएम के पास पहले की तरह पूरा सुरक्षा काफिला रहेगा। केजरीवाल की जेड प्लस सुरक्षा बरकरार रहेगी।

गृह मंत्रालय ने सुरक्षा समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। आईबी के इनपुट है कि केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों से जान का खतरा है। दिल्ली चुनाव के दौरान पंजाब पुलिस की ओर से भी गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस से यह इनपुट साझा किए गए थे। यहां तक की केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जवानों की सुरक्षा टुकड़ी तैनात करने पर भी सियासी बवाल हुआ था।

आईपीएस की बेटी निकली सोना तस्कर

» कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की बढ़ी मुश्किलें

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बेंगलुरू। आईपीएस अधिकारी की बेटी और कन्नड़ अभिनेत्री और रान्या राव की गिरफ्तारी की जांच में पता चला कि वह सोने की तस्करी नेटवर्क का हिस्सा थी और दुबई से बेंगलुरू तक सामान की तस्करी के लिए भारी कमीशन लेती थी। जांच में पता चला है कि रान्या राव सरगनाओं के इशारे पर सोने की तस्करी कर रही थी और अंतरराष्ट्रीय गिरोह का गठजोड़ बहुत गहरा था।

सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्री इतनी अमीर नहीं थी कि 17.29 करोड़ रुपये का सोना खरीद सके। अधिकारियों ने पाया कि अभिनेत्री को दुबई से बेंगलुरू तक एक किलोग्राम सोने की तस्करी करने के लिए 4 लाख से 5 लाख रुपये का कमीशन मिला था। सरगनाओं ने उसे सोने की तस्करी में शामिल किया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह एक सेवारत आईपीएस अधिकारी की बेटी है और इसका फायदा उठाकर तस्करी को अंजाम दे सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों को इसमें बेंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कर्मचारियों की संलिप्तता का भी संदेह है।

ईडी करेगा आगे की जांच

जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि रान्या राव ने सोना किसे सौंपा। अधिकारी रान्या राव के बैंक खातों से डाटा एकत्र कर रहे हैं और पिछले दो वर्षों के लेन-देन का विश्लेषण कर रहे हैं। उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और नेटवर्क के बारे में सुराग पाने के लिए फोन से जानकारी एकत्र की जा रही है। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि रान्या राव से हवाई अड्डे और उसके आवास से भारी मात्रा में सोना और नकदी जब्त होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले को अपने हाथ में ले सकता है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारी उनके आवास से जब्त की गई 2.67 करोड़ रुपये की कथित नकदी की जानकारी ईडी के साथ साझा कर रहे हैं।

मुंबई में धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहेगा जारी

» सुप्रीम कोर्ट ने काम रोकने से किया इनकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज धारावी पुर्नविकास परियोजना के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं, कोर्ट ने अदाणी ग्रुप के पक्ष में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने से भी इनकार कर दिया।

सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने काम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की, जिसमें सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। यूएई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि परियोजना पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें कुछ रेलवे क्वार्टरों को ध्वस्त करना भी शामिल है।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। महाराष्ट्र कार्यालय :- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार : सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार : संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट : हसन जैदी, दूरभाष : 0522- 4078371 | Email : daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in | RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।